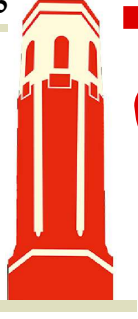


- देहरादून
- वर्ष 34
- अंक 224
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00



दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

शुद्धिकरण मामला: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर मुकदमा

हमारे संवाददाता

बेंगलुरु/देहरादून। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्लानी रैली के बाद कथित शुद्धिकरण अनुष्ठान कराने के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट सहित अन्य लोगों के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर ली है। शिकायत 31 अगस्त 2026 को विधान सौध पुलिस थाने में दाखिल की गई थी।

शिकायत 31 अगस्त 2026 को विधान सौध पुलिस थाने में दाखिल की गई थी। शिकायतकर्ता टी.आर. रामप्पा (आदिवासी कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष) हैं। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 8 अगस्त को हल्लानी के रामलीला मैदान में खड़गे की जनसभा के बाद 10 अगस्त को उसी स्थान पर शुद्धिकरण अनुष्ठान कराया गया। आरोप है कि यह कृत्य जातिगत भेदभाव और छुआछूत की मानसिकता को दर्शाता है। शिकायतकर्ता ने महेंद्र भट्ट पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस घटना का सार्वजनिक रूप से बचाव और समर्थन किया, जिससे सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने शिकायत प्राप्त करने के बाद कानूनी राय ली और 4 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को दोपहर 1 बजे जीरो एफआईआर दर्ज की। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा



196(1)(बी) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं।

शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस

तरह की घटनाओं पर कार्रवाई न होने से जातिगत पूर्वाग्रह को बढ़ावा मिल सकता है और संवैधानिक मूल्यों को खतरा पैदा हो सकता है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए

वीडियो रिकॉर्डिंग, मीडिया रिपोर्ट्स और गवाहों के बयान एकत्र करने को कहा है। यह जीरो एफआईआर अब उत्तराखंड पुलिस को भेजी जाएगी, जहां आगे की जांच की जाएगी।

बेचेहरा दल, बेहिसाब चंदा !

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अस्तित्व चुनाव, विचारधारा और जनता के बीच सक्रियता से जुड़ा होता है। लेकिन देश की चुनावी राजनीति में एक ऐसा विरोधाभास सामने आया है, जिसने राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कुछ छोटे और गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खातों में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान करोड़ों रुपये का चंदा पहुंचा, जबकि चुनावी राजनीति में उनकी मौजूदगी बेहद सीमित रही। चुनाव आयोग के रिकार्ड में ऐसे दलों की संख्या हजारों में रही है। इनमें से कुछ पार्टियों को मिले चंदे की मात्रा इतनी बड़ी बताई गई कि वह कई स्थापित राजनीतिक दलों की फंडिंग से भी आगे निकल गई।

सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इन दलों को कितना पैसा मिला। असली सवाल यह है कि जिस राजनीतिक संगठन की जमीन पर मौजूदगी दिखाई नहीं देती, उसके खाते में इतना पैसा पहुंचा कैसे? कई पड़तालों में ऐसे छह दलों का उल्लेख किया गया है,

जिन्हें बड़ी रकम चंदे के तौर पर मिली। लेकिन इनमें से कई दल चुनावी गतिविधियों में उसी अनुपात में सक्रिय नजर नहीं आए। यही विरोधाभास अब राजनीतिक

◆ न सांसद, न विधायक, चुनावी मैदान में मामूली मौजूदगी और करोड़ों की बारिश
◆ चुनावी मैदान से गायब छोटी पार्टियों के खातों में छप्परफाड़ फंड
◆ 2023-24 में गैर-मान्यता प्राप्त दलों की तिजोरी हो गई है लबालब
◆ छोटे दलों के खातों में सैकड़ों करोड़, राजनीतिक सक्रियता भी नहीं

फंडिंग की मौजूदा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राजनीतिक दलों की आय और चंदे की जानकारी चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत की जानी होती है। आयोग अपनी वेबसाइट पर राजनीतिक दलों की उपलब्ध कराता है। भारत में किसी राजनीतिक संगठन का पंजीकरण होना और उसका चुनाव में प्रभावी राजनीतिक दल बन जाना दो अलग-अलग बातें हैं। लेकिन विशेषज्ञों की चिंता उन मामलों को लेकर

1700 करोड़ रुपये का चंदा

वित्त वर्ष 2023-24 में देश की कुछ छोटी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां चंदा जुटाने के मामले में बड़े-बड़े स्थापित दलों से आगे निकलती दिखाई देती हैं। हैरानी की बात यह है कि इन दलों के पास न कोई लोकसभा सांसद है और न कोई विधायक। चुनावी राजनीति में भी इनकी सक्रियता बेहद सीमित रही है, लेकिन इनके खातों में करोड़ों रुपये का चंदा पहुंचा। आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात की आम जनमत पार्टी को करीब 620 करोड़ रुपये, सत्यवादी रक्षक पार्टी को 330 करोड़ रुपये और न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी को करीब 200 करोड़ रुपये चंदा मिला। वहीं स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, जिसे एक पेपर पार्टी के रूप में बताया गया है, को 219 करोड़ रुपये, भारतीय नेशनल जनता पार्टी को 191 करोड़ रुपये और गरीब कल्याण पार्टी को करीब 138 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यानी इन छह दलों को मिलाकर करीब 1700 करोड़ रुपये का चंदा मिला। इसके मुकाबले कांग्रेस को इसी अवधि में करीब 288 करोड़ रुपये चंदा मिलने का आंकड़ा सामने रखा जा रहा है।

है जहां राजनीतिक गतिविधि और आर्थिक लेनदेन के बीच भारी असमानता दिखाई देती है।

ऐसे मामलों में यह आशंका उठती रही है कि कहीं कुछ संस्थाओं का इस्तेमाल केवल राजनीतिक चंदे के नाम पर धन के लेनदेन के लिए तो नहीं किया जा रहा। मीडिया रिपोर्टों और जांच एजेंसियों के सामने पहले भी ऐसे आरोप आए हैं कि

कुछ चंदे का इस्तेमाल कथित तौर पर फर्जी राजनीतिक चंदे, टैक्स से जुड़ी गड़बड़ियों और धन को इधर-उधर करने के लिए किया गया। हालांकि किसी विशेष दल को मनी लान्डिंग, हवाला या टैक्स चोरी में शामिल मान लेना तब तक उचित नहीं होगा जब तक जांच या न्यायिक प्रक्रिया से इसकी पुष्टि न हो।

राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता का

सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रमुख संस्थान हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय दलों ने भी 20 हजार रुपये से अधिक के दान के रूप में हजारों करोड़ रुपये घोषित किए थे। एके विश्लेषण के अनुसार राजनीतिक दलों की फंडिंग का बड़ा हिस्सा बड़े दानदाताओं और विभिन्न औपचारिक चैनलों से आता रहा है। लेकिन जब कोई छोटा दल अचानक बड़ी रकम प्राप्त करता है और उसके बाद उसके चुनावी प्रदर्शन, संगठनात्मक गतिविधियों अथवा सार्वजनिक उपस्थिति में उसका कोई स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखता, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है यह पैसा राजनीति में गया या सिर्फ राजनीतिक दल के खाते से होकर गुजरा?

राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को संसाधन उपलब्ध कराना है, न कि ऐसी वित्तीय संरचनाओं को जन्म देना जिनका वास्तविक राजनीतिक उद्देश्य ही अस्पष्ट हो जाए। हाल

►► शेष पृष्ठ 7 पर

दून वैली मेल

संपादकीय

गुलदस्ता नहीं, व्यवस्था चाहिए

आज शिक्षक दिवस है। स्कूलों में समारोह होंगे, शिक्षकों को सम्मान मिलेगा, सोशल मीडिया पर गुरु की महिमा के संदेश छाप रहेंगे। मंचों से शिक्षक को राष्ट्र निर्माता बताया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन शिक्षक दिवस के इस शोर के बीच एक सवाल भी पूछा जाना चाहिए जिस शिक्षक के कंधों पर देश का भविष्य रखा है, क्या व्यवस्था ने उसके कंधों का बोझ कम किया है? पहाड़ के दूरस्थ गांवों में विद्यालय आज भी केवल पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि गांव के अस्तित्व की निशानी हैं। जहां पलायन ने घरों के दरवाजे बंद कर दिए, वहां स्कूल की घंटी गांव में जीवन की आखिरी आवाज बनकर रह गई है। लेकिन जब स्कूल में शिक्षक ही पर्याप्त नहीं होंगे, जब बच्चों की संख्या लगातार घटती जाएगी और जब शिक्षक को पढ़ाने से ज्यादा कागजी और गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियों में उलझा दिया जाएगा, तब शिक्षा का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? विडंबना देखिए। हम शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहते हैं और उसी शिक्षक को कभी जनगणना, कभी चुनाव, कभी सर्वे, कभी ऑनलाइन आंकड़ों और कभी दूसरे प्रशासनिक कामों में लगा देते हैं। सवाल यह नहीं कि ये काम जरूरी हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या हर जरूरी काम शिक्षक से ही कराया जाना जरूरी है? शिक्षक का मूल काम बच्चों को पढ़ाना है। उसे वही करने दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड की शिक्षा समस्या को केवल स्कूल भवन, स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। यहां शिक्षा का सवाल सीधे पलायन और गांवों के भविष्य से जुड़ा है, जिस गांव में अच्छा स्कूल नहीं होगा, वहां परिवार बच्चों के भविष्य के लिए शहर की ओर जाएंगे। बच्चे जाएंगे तो गांव खाली होगा। गांव खाली होगा तो खेत, संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी। इसलिए पहाड़ के विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति महज सरकारी पद भरना नहीं है। यह गांव को बचाने की नीति है। दुर्गम क्षेत्रों में तैनात शिक्षक को सुविधाएं, आवास, बेहतर संसाधन और सम्मानजनक कार्य वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। पहाड़ में शिक्षक को भेज देना पर्याप्त नहीं, उसे वहां टिके रहने लायक व्यवस्था देना भी उतना ही जरूरी है। शिक्षक दिवस पर गुलदस्ता देने में कोई बुराई नहीं, लेकिन असली सम्मान तब होगा जब शिक्षक से कहा जाएकृपा पढ़ाइए, बाकी व्यवस्था हम संभालेंगे। आज तकनीक तेजी से बदल रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर डिजिटल शिक्षा तक सब कुछ कक्षा में प्रवेश कर रहा है। लेकिन मशीन जानकारी दे सकती है, शिक्षक विवेक पैदा करता है। इंटरनेट उत्तर दे सकता है, शिक्षक सवाल करना सिखाता है। इसलिए शिक्षा का भविष्य तकनीक और शिक्षक के संघर्ष में नहीं, दोनों के सहयोग में है। शिक्षक दिवस का अवसर हमें यह याद दिलाने आया है कि कक्षा मजबूत होगी तो समाज मजबूत होगा और कक्षा तभी मजबूत होगी जब शिक्षक को कर्मचारी नहीं, शिक्षा व्यवस्था की केंद्रीय शक्ति माना जाएगा। आज शिक्षक को सम्मानित करते समय एक संकल्प भी होना चाहिए, गुलदस्ते कम, सुविधाएं ज्यादा, भाषण कम, संसाधन ज्यादा, आदेश कम, भरोसा ज्यादा। क्योंकि उत्तराखंड का भविष्य केवल सचिवालय में बनने वाली नीतियों से तय नहीं होगा। उसका भविष्य उन पहाड़ी स्कूलों की कक्षाओं में तय होगा, जहां कोई शिक्षक आज भी सीमित साधनों के बीच बच्चों को बेहतर कल का सपना देखना सिखा रहा है। उस शिक्षक को सलाम तभी सार्थक होगा, जब व्यवस्था उसके साथ खड़ी दिखाई दे।



मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को दी शुभकामनाएं

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में महान शिक्षाविद् एवं पूर्व राष्ट्रपति 'भारत रत्न' डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन भारतीय शिक्षा, संस्कृति और मानवीय मूल्यों का प्रेरणास्रोत है। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व आज भी शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रेरित करता है।

मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षक नई पीढ़ी को ज्ञान, संस्कार और जीवन-मूल्यों से समृद्ध कर उन्हें सही दिशा प्रदान करते हैं। राष्ट्र एवं समाज निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

दलों के बीच राजनीतिक 'शब्दयुद्ध' और तेज

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कथित शुद्धिकरण, हवन-यज्ञ और उसके बाद उठे राजनीतिक विवाद की तपिश अब प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकलने की तैयारी में है। विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहे राज्यों में कांग्रेस इस प्रकरण को सिर्फ उत्तराखंड की स्थानीय घटना के तौर पर नहीं, बल्कि भाजपा शासन में सामाजिक सौहार्द, प्रशासनिक निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों पर उठ रहे सवालों के उदाहरण के तौर पर पेश कर सकती है। उत्तराखंड में शुरू हुआ विवाद कांग्रेस के लिए एक ऐसा राजनीतिक हथियार बन सकता है, जिसे वह चुनावी राज्यों में भाजपा के खिलाफ अपने बड़े नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश करे। पार्टी के सामने चुनौती यह है कि स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श से कैसे जोड़ा जाए। रामलीला मैदान प्रकरण कांग्रेस को इसी के लिए एक नया संदर्भ दे सकता है।

कांग्रेस पहले ही उत्तराखंड में इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि धार्मिक भावनाओं से जुड़े विवाद में प्रशासन का रवैया निष्पक्ष नहीं रहा और सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा की ओर से इन आरोपों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताया जा सकता है। यही टकराव अब कांग्रेस की रणनीति का आधार बन सकता है। पार्टी इस सवाल को दूसरे राज्यों तक ले

जा सकती है कि क्या सत्ता और धर्म के सवाल पर प्रशासन का रवैया समान रहता है? क्या राजनीतिक प्रभाव रखने वालों पर कानून उसी तरह लागू होता है जैसे आम नागरिकों पर? यानी स्थानीय विवाद को कांग्रेस एक बड़े सवाल में बदलने की कोशिश करेगी।

आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला केवल सरकारों के कामकाज तक सीमित नहीं

◆ शुद्धिकरण विवाद की आंच अब दूसरे राज्यों तक पहुंचेगी
◆ उत्तराखंड में उठी विंगारी को चुनावी मुद्दा बनाएगी कांग्रेस
◆ दूसरे राज्यों में भाजपा के खिलाफ नैरेटिव को धार देगी

रहने वाला। रोजगार, महंगाई, किसान, महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय के साथ-साथ सामाजिक ध्रुवीकरण और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता भी विपक्ष के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड का विवाद कांग्रेस को इसी मोर्चे पर भाजपा को घेरने का मौका देता है।

कांग्रेस की रणनीति यदि आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड के घटनाक्रम को दूसरे राज्यों में उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। पार्टी का संदेश यह हो सकता है कि भाजपा के शासन में धार्मिक पहचान को राजनीतिक संघर्ष का औजार बनाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए यह

रणनीति जोखिम से खाली नहीं होगी। भाजपा इसे धर्म और आस्था के खिलाफ कांग्रेस की राजनीति बताकर पलटवार कर सकती है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच राजनीतिक शब्दयुद्ध और तेज होने की संभावना है।

भाजपा के लिए चुनौती यह नहीं होगी कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितना बड़ा बनाती है। असली चुनौती यह होगी कि जनता के बीच इस घटनाक्रम की धारणा क्या बनती है। यदि विवाद लगातार सुर्खियों में रहता है और कांग्रेस इसे कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक निष्पक्षता तथा सामाजिक सौहार्द के सवाल से जोड़ने में सफल होती है, तो भाजपा को रक्षात्मक स्थिति में आना पड़ सकता है। विशेषकर उन राज्यों में जहां पहले से ही सामाजिक और धार्मिक मुद्दे चुनावी बहस का हिस्सा हैं, कांग्रेस इस प्रकरण को अपने अभियान में प्रतीकात्मक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर सकती है।

कांग्रेस के लिए इस मुद्दे की राजनीतिक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह इसे किस भाषा में पेश करती है। यदि इसे केवल शुद्धिकरण विवाद तक सीमित रखा गया तो इसका असर उत्तराखंड तक ही रह सकता है। लेकिन यदि पार्टी इसे सत्ता के संरक्षण में सामाजिक विभाजन बनाम संवैधानिक लोकतंत्र के फ्रेम में रखती है, तो इसका दायरा बड़ा हो सकता है। यही कारण है कि उत्तराखंड कांग्रेस के स्थानीय

►► शेष पृष्ठ 7 पर

दिल्ली के 'दिग्गजों' से गरमाएगा पहाड़

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन सियासी रणभूमि सजने लगी है। प्रदेश की सियासत अब धीरे-धीरे स्थानीय नेताओं के दायरे से निकलकर राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथों में जाती दिखाई दे रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने बड़े चेहरों को उत्तराखंड के मैदान में उतारने की तैयारी में हैं। राष्ट्रीय नेताओं के प्रस्तावित दौरों ने साफ संकेत दे दिया है कि 2027 का चुनाव अब केवल देहरादून की राजनीतिक बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा इसी चुनावी सक्रियता की अहम कड़ी माना जा रहा है। संगठनात्मक बैठकों से लेकर अलग-अलग सामाजिक समूहों के कार्यक्रमों तक उनकी सक्रियता को भाजपा की चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत राष्ट्रीय नेतृत्व के कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश में माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी सितंबर के साथ उत्तराखंड में चुनावी राजनीति का राष्ट्रीय चरण शुरू होता दिखाई दे रहा है।

राष्ट्रीय नेताओं का कोई भी दौरा अब महज संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं माना जाएगा। किस जिले को चुना गया, किस नेता को मंच पर जगह मिली, किन मुद्दों को उठाया गया और कितनी भीड़ जुटी कृहर तस्वीर और हर बयान के राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। भाजपा जहां अपने संगठन

और सरकार की उपलब्धियों को लेकर मैदान में उतरने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुद्दों को धार देने की कोशिश करेगी। इसका सीधा असर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। एक दल का कार्यक्रम दूसरे दल पर दबाव बढ़ाएगा और फिर उसके जवाब में दूसरा दल मैदान में उतरेगा। इस तरह आने वाले महीनों में कार्यक्रम, बयान, आरोप और पलटवार उत्तराखंड की राजनीति का रोजमर्रा का हिस्सा बनने वाले हैं।

भाजपा के लिए 2027 का चुनाव

◆ 2027 की जंग का काउंटडाउन हुआ शुरू, भाजपा की हैट्रिक पर नजर
◆ कांग्रेस की सत्ता वापसी की बेचौनी, राष्ट्रीय नेताओं के दौरों की सियासत
◆ उत्तराखंड में चुनावी राजनीति का राष्ट्रीय चरण अभी से हो गया है शुरू

ऐतिहासिक महत्व रखता है। पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार अपने कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाएगी, जबकि संगठन बूथ स्तर तक अपनी मशीनरी को मजबूत करने में जुटा है। लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। स्थानीय स्तर पर विधायकों को लेकर नाराजगी, टिकट के दावेदारों की बढ़ती संख्या, क्षेत्रीय असंतोष और सरकार के खिलाफ उठने वाले मुद्दे भाजपा के लिए परीक्षा बन सकते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की सक्रियता को संगठन की ग्राउंड रिपोर्ट से भी जोड़कर देखा जा रहा

है।

कांग्रेस के लिए यह चुनाव सत्ता में वापसी का बड़ा अवसर है। पाटरगु यदि भाजपा विरोधी मतों को एकजुट कर पाती है और स्थानीय मुद्दों को प्रभावी तरीके से चुनावी नैरेटिव में बदलती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाएं, पलायन, महंगाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, आपदा, सड़कें, शिक्षा और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को कांग्रेस लगातार उठाती रही है। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक एकजुटता और नेतृत्व का सवाल है। राष्ट्रीय नेताओं की सक्रियता तभी प्रभावी होगी, जब उसका फायदा बूथ स्तर के संगठन तक पहुंचे।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि बड़े नेताओं के आने के बाद चुनाव का एजेंडा किस दिशा में जाएगा? क्या 2027 का चुनाव उत्तराखंड के स्थानीय सवालों पर लड़ा जाएगा या फिर भाजपा-कांग्रेस के बीच राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी लड़ाई का विस्तार बन जाएगा? पहाड़ का मतदाता सड़क, रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती चाहता है। मैदान का मतदाता रोजगार, महंगाई, कानून-व्यवस्था और शहरी सुविधाओं को लेकर सवाल पूछ रहा है। यदि राष्ट्रीय नेतृत्व इन स्थानीय सवालों को अपने चुनावी भाषणों में जगह देता है तो चुनाव का रंग अलग होगा। लेकिन यदि मुकाबला केवल केंद्र की राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दों तक सिमट गया तो उत्तराखंड के असली सवाल फिर पीछे छूट सकते हैं।

►► शेष पृष्ठ 7 पर

सोलर सिंचाई योजना से ग्राम जर्यूड़ा में बढ़ी खेती और किसानों की आय

अल्मोड़ा (आरएनएस)। भैसियाछना विकासखंड के ग्राम जर्यूड़ा (दसौं) में स्थापित सोलर सिंचाई योजना किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। वर्षा पर निर्भर रहने वाले किसानों को अब सालभर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो रहा है, जिससे खेती का रकबा, उत्पादन और आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों वाले अल्मोड़ा जिले में अधिकांश कृषि भूमि जल स्रोतों से ऊंचाई पर स्थित होने के कारण पारंपरिक ग्रेविटी आधारित सिंचाई कई स्थानों पर संभव नहीं हो पाती। ऐसे में सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई योजना किसानों के लिए प्रभावी विकल्प बनकर उभरी है। जर्यूड़ा (दसौं) गांव में योजना शुरू होने से पहले किसान मुख्य रूप से वर्षा जल पर निर्भर थे। पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं होने से कृषि उत्पादन प्रभावित होता था। अब सोलर पम्प, टैंक और पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक नियमित पानी पहुंच रहा है, जिससे किसानों को सालभर सिंचाई की सुविधा मिल रही है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सौर ऊर्जा से संचालित होने के कारण किसानों को डीजल, पेट्रोल या बिजली पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ता। इससे खेती की लागत कम हुई है और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिली है। वर्तमान में इस योजना से करीब चार हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जा रही है, जबकि 12 परिवार सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। सिंचाई सुविधा मिलने से किसानों को समय पर खेती करने और बेहतर उत्पादन प्राप्त करने का अवसर मिला है।

प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग में बाल वैज्ञानिकों ने दिखाई प्रतिभा

पिथौरागढ़ (आरएनएस)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विण में द्वितीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। मंगलवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी डीएल आर्य और जिला विज्ञान समन्वयक डॉ. विकास पंत ने किया। इस वर्ष विज्ञान प्रीमियर लीग का मुख्य विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवीकरणीय ऊर्जा रहा। ब्लॉक विज्ञान समन्वयक करन सिंह थापा ने सीनियर और जूनियर वर्ग की प्रतियोगिता के बारे में बताया। सीनियर वर्ग में न्यू बीयर शिवा के तनिष्क भंडारी ने प्रथम, स्टेफोर्ड पब्लिक स्कूल के हृदयांश जोशी ने द्वितीय और न्यू बीयर शिवा के सत्यम जोशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में न्यू बीयर शिवा के राजवर्धन सिंह प्रथम रहे, जबकि स्टेफोर्ड पब्लिक स्कूल के देवांग पांडेय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। चयनित बाल वैज्ञानिक अब जिले में आयोजित प्रतियोगिता में विकासखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान मुकेश उपाध्याय, ब्लॉक अकादमिक समन्वयक राजेंद्र राम, नीरज जोशी, मनोज पांडे, दीपा खाती, ज्योति पाठक, दीक्षा पाठक, निकांशा चंद, कमला पाल, सौम्य चंद, राजेंद्र पांडेय समेत दर्जनों शिक्षक मौजूद रहे।

मोरी क्षेत्र में कमजोर नेटवर्क से ग्रामीण परेशान

उत्तरकाशी (आरएनएस)। विकासखंड मोरी के दूरस्थ क्षेत्रों में बीएसएनएल मोबाइल नेटवर्क की खराब स्थिति ग्रामीणों के लिए लगातार परेशानी का कारण बनी हुई है। कई पुराने टावरों की रेंज और क्षमता कम होने और नए लगाए गए टावरों के अब तक संचालित नहीं होने से क्षेत्र में संचार व्यवस्था प्रभावित है। ग्रामीणों को मोबाइल नेटवर्क के अभाव में जरूरी फोन कॉल करने के साथ ही ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग और अन्य इंटरनेट आधारित सेवाओं का लाभ लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर भाजपा के मनमोहन सिंह चौहान ने बीएसएनएल उत्तराखंड के महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में नेटवर्क व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। उन्होंने महाप्रबंधक से जनहित को देखते हुए मोरी क्षेत्र में लगाए गए नए टावरों को जल्द संचालित कराने और पुराने टावरों की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी सुधार कराने का अनुरोध किया।

शक्ति नहर पर सुरक्षा के लिए लगेगा तार जाल, यूजेवीएनएल ने शुरु की कार्रवाई

विकासनगर (आरएनएस)। विकासनगर में शक्ति नहर को सुरक्षित बनाने के लिए शासन स्तर से पहल शुरू हो गई है। नहर में गिरने से हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए नहर के दोनों किनारों पर तार-बाड़ लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द ही यूजेवीएनएल नहर के दोनों तरफ सुरक्षा जाल लगाने का कार्य शुरू करेगा। दरअसल, विकासनगर में शक्तिनहर में डाकपत्थर से लेकर ढकरानी तक सुरक्षा के लिए न तो जाल लगे हैं और न ही पैराफिट। नहर के दोनों तरफ सड़क है और बड़ी आबादी निवास करती है। सड़क दोनों तरफ काफी यातायात रहता है, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम न होने के कारण शक्तिनहर में हादसे होते रहते हैं। हाल ही में एक युवक कार सहित नहर में समा गया था। चार दिन बार उसका शव बरामद हुआ था। इससे पहले भी शक्ति नहर में कई हादसे हो चुके हैं। कई लोग नहर में कूदकर जान दे चुके हैं। यही नहीं मनुष्यों के साथ ही जानवर भी कई बार शक्ति नहर में गिरकर जान गवां चुके हैं। लगातार हादसों के बाद शक्तिनहर के दोनों तरफ सुरक्षा के लिए तार जाल और पैराफिट लगाने की मांग हो रही है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नहर के दोनों तरफ सुरक्षा के लिए तार जाल लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस संबंध में यूजेवीएनएल के उपमहाप्रबंधक यूजेवीएनएल इंद्र मोहन सिंह करासी ने अधिशासी अभियंता को तत्काल सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नहर के दोनों तरफ सुरक्षा तार बाड़ के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है, जिससे कि आगे का कार्य शुरू किए जा सके।

चुनावी दहलीज पर ‘उबला’ उत्तराखंड

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। हल्द्वानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद कथित शुद्धिकरण को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने के बजाय अब उत्तराखंड की सियासत के केंद्र में पहुंच गया है। कांग्रेस ने मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर 7 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न किया जाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार का संबंधित धार्मिक संगठन के साथ कहीं न कहीं गठजोड़ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान ने विवाद को और राजनीतिक रंग दे दिया है। गोदियाल का कहना है कि यदि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती तो अब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होती। लेकिन सरकार की चुप्पी और कार्रवाई का अभाव कई सवाल खड़े कर रहा है।

गोदियाल ने सवाल उठाया कि सार्वजनिक स्थल पर आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम के बाद कथित शुद्धिकरण जैसी गतिविधि को लेकर शिकायतें सामने आने के बावजूद सरकार कार्रवाई से पीछे क्यों हट रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मामला केवल एक मैदान में पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठान का नहीं है। सवाल यह है कि क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा के बाद उस स्थल को अपवित्र मानकर शुद्धिकरण किया जाना सामाजिक और राजनीतिक रूप से स्वीकार्य है? कांग्रेस इसी सवाल को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार अगर निष्पक्ष है तो उसे बिना किसी दबाव के पूरे मामले की जांच करानी चाहिए और जो भी दोषी हैं, उनके

खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को विधानसभा और पार्टी कार्यालयों की बयानबाजी से निकालकर सड़क पर ले जाने का फैसला किया है। पार्टी ने 7 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच का आह्वान किया है। पार्टी की कोशिश है कि हल्द्वानी के विवाद को केवल स्थानीय घटना न रहने दिया जाए, बल्कि इसे सामाजिक सम्मान, संविधान और सरकार की जवाबदेही के बड़े मुद्दे के रूप में जनता के सामने रखा जाए। कांग्रेस के लिए यह आंदोलन इसलिए भी

◆ कांग्रेसी मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर दिखाएंगी आर-पार का दम
◆ बलित सम्मान के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी को कांग्रेस ने बनाया लाल
◆ कांग्रेस पार्टी ने जांच व एफआईआर की मांग पर प्रदेश सरकार को घेरा

महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को आक्रामक मोड़ में लाने की कोशिश कर रही है।

विवाद अब सीधे भाजपा सरकार की जवाबदेही से जुड़ गया है। कांग्रेस लगातार पूछ रही है कि आखिर सरकार ने कथित शुद्धिकरण मामले में क्या कार्रवाई की? क्या पूरे घटनाक्रम की जांच हुई? जिम्मेदार लोगों की पहचान हुई या नहीं? और अगर पहचान हुई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाजपा के लिए चुनौती यह है कि वह कांग्रेस के आरोपों को सिर्फ राजनीतिक बयान बताकर खारिज करे या पूरे मामले पर अपना स्पष्ट पक्ष सामने रखे। क्योंकि कांग्रेस ने अब एक ऐसा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब केवल हल्द्वानी तक सीमित नहीं रहेगा।

खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद शुरू हुआ विवाद अब कुमाऊं से निकलकर

देहरादून पहुंच चुका है। कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास कूच के जरिए सीधे सरकार के दरवाजे पर दस्तक देने जा रही है। दिलचस्प यह है कि इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के हल्द्वानी दौरे और प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को लेकर भी राजनीतिक हलचल तेज है। ऐसे में कांग्रेस का आंदोलन और भाजपा का संगठनात्मक कार्यक्रम एक-दूसरे के समानांतर राजनीतिक संदेश देने की स्थिति बना रहे हैं।

कांग्रेस जहां शुद्धिकरण विवाद को सामाजिक सम्मान और संवैधानिक मूल्यों से जोड़ रही है, वहीं भाजपा के सामने संगठन को चुनावी रूप से मजबूत करने के साथ विपक्ष के हमलों का जवाब देने की चुनौती है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले अभी कुछ समय दूर हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। ऐसे में हल्द्वानी का विवाद कांग्रेस के लिए भाजपा को घेरने का नया हथियार बन गया है। कांग्रेस की रणनीति साफ है रामलीला मैदान से उठे सवाल को मुख्यमंत्री आवास तक ले जाना। अब देखना यह है कि 7 सितंबर को कांग्रेस का आंदोलन कितना बड़ा रूप लेता है और सरकार इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल हल्द्वानी का रामलीला मैदान उत्तराखंड की राजनीति का नया अखाड़ा बन चुका है।

एक तरफ कांग्रेस कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है, दूसरी तरफ भाजपा संगठनात्मक ताकत के साथ मैदान में उतर रही है और इस पूरे राजनीतिक टकराव के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है। शुद्धिकरण किसका हुआ और अब सरकार की चुप्पी किस चीज को साफ कर रही है?

पटना, भुवनेश्वर और हैदराबाद संभाग का दबदबा, सांस्कृतिक संध्या में दिखी देश की विविधता

हरिद्वार (आरएनएस)। रोशनाबाद स्थित पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय में चल रही नवोदय विद्यालय समिति की राष्ट्रीय स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता-2026 में खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन किया।

वंदना कटारिया स्टेडियम में हुए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन के साथ खेल भावना और अनुशासन की मिसाल पेश की। प्रतियोगिता के दौरान अलग-अलग आयु वर्गों में कई मुकाबले एकतरफा रहे तो कुछ में कड़ा संघर्ष देखने को मिला। प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर-17 वर्ग में शिलांग और पुणे संभाग के बीच मुकाबला हुआ।

शिलांग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-0 से जीत दर्ज की। अंडर-19 वर्ग में पटना ने पुणे को 9-0 से हराया। भोपाल और अहमदाबाद के बीच हुए मुकाबले में भोपाल ने 3-1 से जीत हासिल की। चंडीगढ़ और भुवनेश्वर के मुकाबले में भुवनेश्वर ने 4-0 से बाजी मारी, जबकि लखनऊ ने हैदराबाद को 5-3 से हराया। अंडर-14 वर्ग में हैदराबाद ने पुणे को 1-

0 से और पटना ने अहमदाबाद को 9-0 से पराजित किया।

तीन सितंबर को खेले गए मुकाबलों में हैदराबाद ने अहमदाबाद को 10-0 से हराया। चंडीगढ़ और लखनऊ के बीच हुए मुकाबले में लखनऊ ने 1-0 से जीत दर्ज की।

भुवनेश्वर ने भोपाल को 9-0 से हराया। पटना ने शिलांग को 2-0 से मात दी। अंडर-19 वर्ग में पटना ने भोपाल को 9-0 और भुवनेश्वर ने लखनऊ को 5-0 से पराजित किया।

अंडर-14 वर्ग में लखनऊ ने हैदराबाद को 5-0 और पटना ने चंडीगढ़ को 6-0 से हराया। विद्यालय के प्राचार्य सुनीत कुमार गुप्ता ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए टीम मैनेजर, अनुरक्षकों, रेफरी और अंपायरों के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि विभिन्न संभागों से आए खिलाड़ियों ने अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना का उत्कृष्ट परिचय दिया।

खेल प्रभारी भरत सिंह और नमिता सिंह ने प्रतियोगिता के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिवहन प्रभारी राजेंद्र सिंह

खोलिया ने सभी टीमों के आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित की। समापन अवसर पर सभी टीम मैनेजरों और अनुरक्षकों को स्मृति चिह्न के साथ पवित्र गंगाजल भेंट किया गया।

उपप्राचार्य लाजपत सिंह ने सभी प्रतिभागियों और आयोजकों का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन पीजीटी भूगोल प्रियंका राय और कक्षा 12 के छात्र आयुष त्रिपाठी ने किया। इस दौरान देहरादून के प्राचार्य आदेश कुमार शर्मा और शामली के उपप्राचार्य शलभ मिश्र भी मौजूद रहे, शाम को विद्यालय के एकेडमिक ब्लॉक में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न संभागों से आए प्रतिभागियों ने लोकगीत, लोकनृत्य और संगीत के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई। नवोदय विद्यालय हरिद्वार की छात्राओं ने गढ़वाली लोकनृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का मूल्यांकन अंजलि सैनी, कमलेश्वर और अर्चना ने किया। मार्च पास्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भुवनेश्वर संभाग को विजेता ट्रॉफी दी गई।

बच्चों की डाइट में प्रोटीन शामिल करने के लिए अपनाएं ये तरीके, रहेंगे सेहतमंद

बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। यह उनके शरीर और दिमाग के विकास में अहम भूमिका निभाता है। प्रोटीन से भरपूर डाइट बच्चों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी बढ़ाती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चे के खाने में प्रोटीन जोड़ सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपका बच्चा सेहतमंद रहेगा, बल्कि उसका विकास भी अच्छा होगा।

दूध और डेयरी उत्पादों का सेवन बढ़ाएं : दूध और डेयरी उत्पाद प्रोटीन का बढ़िया स्रोत होते हैं। बच्चों को रोजाना एक गिलास दूध पिलाने की आदत डालें। इसके अलावा दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद भी उनके खाने में शामिल करें। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें हड्डियों के लिए जरूरी तत्व भी होते हैं। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता तो उसे मिल्क शेक या स्मूदी के रूप में पेश करें, जिससे वह आसानी से दूध और अन्य पोषक तत्व ले सके।

दालें और फलियों को शामिल करें : दालें और फलियां प्रोटीन का एक अहम स्रोत मानी जाती हैं, जो शाकाहारी बच्चों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होती हैं। इनका उपयोग करके आप सूप, सलाद या फिर सब्जी जैसे कई प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। इनका सेवन करने से बच्चे को भरपूर प्रोटीन मिल सकता है और उनकी ऊर्जा भी बढ़ सकती है।

सूखे मेवे और बीजों को दें प्राथमिकता : सूखे मेवे और बीजों में भी प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन्हें बच्चों के खाने में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। बादाम, अखरोट और काजू आदि न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें स्वस्थ वसा भी होती है, जो बच्चे के दिमाग के विकास के लिए जरूरी होती है। इसके अलावा चिया बीज और अलसी के बीज जैसे बीजों का उपयोग करके आप स्मूदी या फिर दही में मिला सकते हैं, जिससे बच्चे को प्रोटीन मिलता रहेगा।

सोयाबीन जैसे विकल्प भी हैं उपयोगी : सोयाबीन एक ऐसा विकल्प है, जो शाकाहारी बच्चों को भरपूर प्रोटीन दे सकता है। इसे कई प्रकार से पकाकर खाया जा सकता है, जैसे टोफू और सोया चंक्स आदि। आप इसे उनकी रोजाना के पसंदीदा व्यंजनों में मिला सकते हैं या इससे बनने वाला दूध भी पीने को दे सकते हैं।

रसोई गैस सिलेंडर के पास न रखें ये चीजें, हो सकता है बड़ा नुकसान

रसोई में गैस सिलेंडर का उपयोग आम है, लेकिन इसके पास कुछ चीजें रखना खतरनाक हो सकता है। अगर आप गैस सिलेंडर को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि, अगर आप रसोई में गैस सिलेंडर के पास कुछ ऐसी चीजें रखते हैं तो इससे आग लगने या अन्य खतरों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि गैस सिलेंडर के पास किन-किन चीजों को नहीं रखना चाहिए।

आग पकड़ने वाले पदार्थ रखें दूर : गैस सिलेंडर के पास कभी भी आग पकड़ने वाले पदार्थ नहीं रखने चाहिए जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेल पॉलिश रिमूवर आदि। ये पदार्थ आग लगने पर तेजी से फैल सकते हैं और बड़े नुकसान का कारण बन सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई बोटलें हों तो उन्हें गैस सिलेंडर से दूर ही रखें और किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके अलावा गैस सिलेंडर के पास लकड़ी, कागज या अन्य आग पकड़ने वाली चीजें भी न रखें।

केमिकल वाली चीजें न रखें : गैस सिलेंडर के पास केमिकल वाली चीजें रखना भी खतरनाक हो सकता है। इनमें सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले तरल पदार्थ, कीटनाशक और अन्य केमिकल शामिल हैं। ये चीजें गैस सिलेंडर के पास रखने से धमाका या आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इन चीजों को गैस सिलेंडर से दूर ही रखें। अगर आपको इनका इस्तेमाल करना हो तो पहले गैस सिलेंडर बंद कर दें और फिर इनका उपयोग करें।

भारी सामान न रखें : गैस सिलेंडर के पास भारी सामान रखना भी सही नहीं है क्योंकि इससे सिलेंडर दब सकता है और गैस रिसने की संभावना बढ़ जाती है। भारी सामान जैसे बर्तन, अनाज या अन्य कोई भी भारी चीजें गैस सिलेंडर के पास न रखें। इससे न केवल गैस सिलेंडर खराब हो सकता है बल्कि आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा गैस सिलेंडर को खुली जगह पर रखें और उसके आसपास हल्की चीजें ही रखें।

बिजली के उपकरण भी हैं नुकसानदायक : गैस सिलेंडर के पास बिजली के उपकरण रखना भी खतरनाक हो सकता है जैसे कि पंखा, हीटर आदि। इन उपकरणों से निकलने वाली गर्मी या चिंगारी आग का कारण बन सकती है इसलिए इन्हें भी गैस सिलेंडर के पास न रखें। अगर कभी भी गैस सिलेंडर में रिसाव हो जाए तो सबसे पहले गैस सिलेंडर को बंद कर दें और फिर गैस सिलेंडर को खुली हवा वाली जगह पर रख दें ताकि गैस धीरे-धीरे खत्म हो जाए।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो सांध्य दैनिक दून वैली मेल के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

—प्रबंधक विज्ञापन

राजनीतिक डैमेज कंट्रोल की ‘अग्निपरीक्षा’

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद रामलीला मैदान में कथित शुद्धिकरण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के हल्द्वानी दौरे से और गरमा गया है। नबीन के प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के लिए हल्द्वानी पहुंचने से पहले कांग्रेस ने भाजपा पर सीधा राजनीतिक हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हल्द्वानी में शुद्धिकरण विवाद पर माफी मांगने आ रहे हैं। हालांकि भाजपा की ओर से नबीन के दौरे को संगठनात्मक कार्यक्रम बताया जा रहा है और उनके दौरे को माफी से जोड़ने की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह नबीन के दौरे को विवाद से जोड़ दिया है, उससे साफ है कि हल्द्वानी में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति अब सिर्फ संगठन की बैठक नहीं रहने वाली। यह बैठक राजनीतिक संदेशों और जवाबी नैरेटिव का बड़ा मंच बन सकती है।

खड़गे की हल्द्वानी सभा के बाद रामलीला मैदान में कथित शुद्धिकरण को लेकर विवाद ने कांग्रेस को भाजपा पर हमला करने का मौका दे दिया। कांग्रेस ने इसे दलित सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ते हुए भाजपा को कठघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित समाज से आने वाले वरिष्ठ नेता की सभा के बाद इस तरह की कार्रवाई का कथित तौर पर होना बेहद गंभीर है। अब कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर नबीन के हल्द्वानी दौरे पर सवाल खड़े कर रही है।

कांग्रेस का कहना है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहले इस पूरे घटनाक्रम पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। पार्टी नेताओं का दावा है कि यदि भाजपा इसे गलत मानती है तो उसे सार्वजनिक रूप से

इसकी निंदा करनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। नबीन का हल्द्वानी दौरा ऐसे समय हो रहा है जब उत्तराखंड की राजनीति धीरे-धीरे 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है। प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में संगठन को चुनावी मोड़ में लाने, बूथ स्तर पर तैयारियों और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की रणनीति पर मंथन की उम्मीद है।

◆‘शुद्धिकरण’ पर घिरी भाजपा, कांग्रेस का तंज-माफी मांगने हल्द्वानी आ रहे नितिन नबीन
◆नबीन के दौरे से गरमाई सियासत, कांग्रेस बोली- खड़गे के अपमान का जवाब दे भाजपा
◆हल्द्वानी बनेगा भाजपा और कांग्रेस के राजनीतिक संदेशों और जवाबी नैरेटिव का बड़ा मंच

लेकिन कांग्रेस ने पहले ही बैठक के राजनीतिक एजेंडे में शुद्धिकरण विवाद को शामिल कर दिया है। यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने चुनौती सिर्फ कार्यकर्ताओं को चुनावी संदेश देने की नहीं होगी। कांग्रेस के हमले का जवाब देना भी राजनीतिक मजबूरी बन सकता है।

यदि भाजपा इस मुद्दे पर चुप रहती है तो कांग्रेस इसे माफी से बचने के रूप में प्रचारित कर सकती है। यदि राष्ट्रीय नेतृत्व इस विवाद पर कोई टिप्पणी करता है तो मामला और राष्ट्रीय सुर्खियों में आ सकता है। कांग्रेस के लिए यह विवाद महज एक स्थानीय घटना नहीं है। पार्टी इसे भाजपा की विचारधारा, सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों से जोड़कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। खड़गे के हल्द्वानी दौरे को कांग्रेस पहले ही कुमाऊं में अपने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के अभियान के रूप में देख रही थी। अब शुद्धिकरण विवाद ने उसे भाजपा पर

हमला करने के लिए एक अतिरिक्त मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस की रणनीति साफ दिखाई दे रही है खड़गे के कथित अपमान को 2027 के चुनावी विमर्श से जोड़ना। भाजपा की ओर से नबीन का दौरा संगठनात्मक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। प्रदेश कार्यसमिति में आगामी चुनाव को लेकर संगठन की दिशा तय होगी। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और विपक्ष के आरोपों का राजनीतिक जवाब देने की रणनीति पर भी चर्चा संभव है। लेकिन कांग्रेस ने नबीन के हल्द्वानी पहुंचने से पहले ही सवाल खड़ा कर दिया हैकृकि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ संगठन की बैठक करने आ रहे हैं या शुद्धिकरण विवाद पर भाजपा का रुख भी स्पष्ट करेंगे?

यही सवाल अब हल्द्वानी की सियासत के केंद्र में है।

कांग्रेस के लिए राजनीतिक गणित भी दिलचस्प है। यदि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस विवाद पर खेद या माफी जैसा कोई बयान देते हैं तो कांग्रेस इसे अपनी राजनीतिक जीत के रूप में पेश कर सकती है। दूसरी तरफ यदि भाजपा इसे विपक्ष की राजनीतिक साजिश बताकर खारिज करती है तो कांग्रेस हमले को और तेज कर सकती है। इसलिए नबीन का हल्द्वानी दौरा भाजपा के लिए संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन के साथ-साथ राजनीतिक डैमेज कंट्रोल की परीक्षा भी बनता दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी में खड़गे आए थे तो कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला था। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी शहर में आ रहे हैं। मंच भाजपा का होगा, लेकिन कांग्रेस ने सवाल पहले ही उछाल दिया है शुद्धिकरण पर जवाब कब?

उत्तराखंड की 2027 की चुनावी लड़ाई में यह विवाद कितना बड़ा मुद्दा बनता है, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि हल्द्वानी की सियासत में खड़गे के बाद नबीन की एंट्री ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है।

शब्द सामर्थ्य -059

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. अभिमान, घमंड, अनुमान 4. बादल, मेघ, जलद (सं) 6. अधिकार वाला, अधिकारी 8. गति, सामंजस्य, समा जाना 10. कारावास, जेल 11. जोर, शक्ति, जान, सांस 12. राजाओं के रहने का भवन 15. मालामाल, अमीर, धनवान 18. नाव खेने का यंत्र 20. ‘खन’ ध्वनि उत्पन्न होना,

पायल आदि का शब्द करना 21. मार डाला हुआ, घायल किया हुआ 22. हमेशा, आवाज 23. आग की लपट, ज्वाला 24. झगड़ा, तकरार 25. हीरा।

ऊपर से नीचे

1. दोषी, अपराधी 3. ताश में नौ अंक वाला पत्ता 4. झंडा, पताका 5. गहरा कीचड़, पंक 7. बूंद, अंश 9. मृत्यु के देवता 13.

संसार, दुनिया, जग 14. हुजूर, जनाब, सम्मान सूचक एक शब्द (उ.) 16. सच्चा, धर्मनिष्ठ, ईमानवाला 17. अनूठा, बांका, अनुपम, छैला 18. आश्रय, शरण 19. साधुवाद, प्रशंसा 20. पटवारी की ऐसी बही जिसमें खेत संबंधी अनेक बातें लिखी जाती है, एक प्रकार का दानेदार संक्रामक रोग 23. गम, मातम, दुख।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 58 का हल

स्मृ	ति		पा	व	क		बे	ल
	र	ज	नी	च	र			दू
मु	स्का	न		न	म	की	न	
सा	र		स			ट	ख	ना
फि		अ	जा	य	ब		रा	जा
र	च	ना		था	ल			य
		धि		र्थ		स	मा	ज
उ	प	कृ	त		आ	वा	ज	
ल्लू		त			ब	ल	रा	म

रवि तेजा की इरुमुडी ने रचा इतिहास, बनी साल की पहली 100 प्रतिशत प्रॉफिट कमाने वाली तेलुगु फिल्म

रवि तेजा की इरुमुडी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. यहां तक की रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक से कड़े मुकाबले के बावजूद इरुमुडी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है और हर दिन करोड़ों कमा रही है. इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दूसरे हफ्ते में भी काफी मजबूत बनी हुई है. वहीं दूसरे मंडे को भी इसने अच्छी कमाई की. इन सबके बीच इसने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

इरुमुडी तेलुगु की फैमिली एंटरटेनर फिल्म है. इसने दूसरे सोमवार यानी 11वें दिन 6.6 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि इसने अपनी रिलीज के बाद से पहली बार दूसरे मंडे को सिंगल डिजिट में कलेक्शन किया है फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़

मजबूत बनाए हुए हैं. इन सबके बीच इरुमुडी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 11 दिनों में कुल 136.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. जबकि इसकी ग्रॉस कमाई 160.66 करोड़ रुपये. फिलहाल फिल्म की रफ्तार को देखते हुए लग रहा है इसमें अभी भी काफी दम है और यह 200 करोड़ रुपये (नेट) का आंकड़ा छू सकती है.

इरुमुडी को 35 करोड़ के बजट में बनाया गया बताया जा रहा है. इस फिल्म ने रिलीज के 11 दिनों में 136.15 करोड़ की नेट कमाई की है. ऐसे में इसने अपनी पूरी लागत वसूलने के साथ ही 101.15 करोड़ का रिटर्न हासिल कर लिया है. जो 289% रिटर्न के बराबर है. अपने बजट से लगभग तीन गुना कमाई कर ये फिल्म सुपर डुपर हिट का दर्जा हासिल कर चुकी है. इसी के साथ ये साल 2026 की पहली तेलुगु फिल्म बन गई है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रवि तेजा की यह फिल्म और कितना आगे जाती है.

इस फिल्म को शिवा निर्वाण ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इसे मैत्री मूवी मेकर्स बैनर के तहत नवीन यरनेनी और वाई रवि शंकर ने प्रोड्यूस किया है. इरुमुडी की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में रवि तेजा के अलावा प्रिया भवानी शंकर, साई कुमार और बेबी नक्षत्र ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं.

कार्ति की सरदार 2' फिल्म 10 सितंबर को होगी रिलीज

दक्षिण भारतीय फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता कार्ति अपनी आगामी फिल्म सरदार 2' के साथ एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। पी.एस. मित्रन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर निर्माताओं ने जारी कर दिया है। फिल्म 10 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। फिल्म के प्रचार अभियान और टीजर को पहले ही दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल चुकी है।

ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, रोमांच और शानदार दृश्य देखने को मिल रहे हैं। कार्ति को एक गुप्त मिशन पर निकले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। कहानी में रहस्य और रोमांच के साथ कई बड़े मोड़ नजर आ रहे हैं। वहीं, अभिनेता एस.जे. सूर्या के साथ कार्ति की भिड़ंत ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है।

सरदार 2' के ट्रेलर में बड़े स्तर पर फिल्माए गए एक्शन दृश्यों के साथ प्रभावशाली दृश्यांकन देखने को मिलता है। फिल्म का पार्श्व संगीत भी ट्रेलर के रोमांच को बढ़ाता है। वहीं, छायांकन ने फिल्म के दृश्यों को भव्य रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

फिल्म को लेकर दर्शकों में खास उत्साह इसलिए भी है, क्योंकि यह लोकप्रिय फिल्म सरदार' की अगली कड़ी है। पहली फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी और अब इसके दूसरे भाग से भी काफी उम्मीदें की जा रही हैं।

फिल्म में मालविका मोहनन मुख्य अभिनेत्री की भूमिका में नजर आएंगी। उनके अलावा आशिका रंगनाथ और योगी बाबू भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

फिल्म का संगीत सैम सी.एस. ने तैयार किया है। इसका निर्माण प्रिंस पिक्चर्स के बैनर तले एस. लक्ष्मण कुमार और ईशान सक्सेना कर रहे हैं।

सरदार 2' को तेलुगु भाषा में भी दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है। तेलुगु संस्करण का प्रदर्शन अनूपूर्ण स्टूडियोज के बैनर के तहत किया जाएगा।

ट्रेलर में नजर आ रहे एक्शन, कार्ति का अलग अंदाज और एस.जे. सूर्या के साथ उनकी टक्कर को देखते हुए सरदार 2' के प्रति दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है। फिल्म 10 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

भोजपुरी सिनेमा को सिर्फ डबल मीनिंग गानों से जोड़ने पर मोनालिसा ने जताई नाराजगी !

मोनालिसा भोजपुरी सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने रीजनल इंडस्ट्री से निकलकर नेशनल टेलीविजन और मनोरंजन की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। लंबे समय से भोजपुरी सिनेमा को लेकर ग्लैमर, डबल मीनिंग गानों और अश्लील कंटेंट की चर्चा होती रही है। इस लेकर मोनालिसा का मानना है कि कुछ गानों या म्यूजिक वीडियो के आधार पर पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक ही नजर से देखना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्मों को लेकर राय बनाने वाले कई लोगों ने शायद असल में फिल्में देखी ही नहीं हैं। मोनालिसा ने कहा, मैं कई सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर इस तरह की बातें सुनती आ रही हूं। मुझे लगता है कि लोगों की सोच फिल्मों से ज्यादा उन म्यूजिक वीडियो की वजह से बनी है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होते हैं और लाखों-करोड़ों व्यूज हासिल करते हैं और उसी के आधार पर वे पूरी इंडस्ट्री को जज करने लगते हैं। मोनालिसा ने कहा, हर भोजपुरी फिल्म को एक ही नजर से देखना ठीक नहीं है। एल्बम और म्यूजिक वीडियो में भले ही ग्लैमर या इस तरह का कंटेंट ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन फिल्मों की कहानी और उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। भोजपुरी फिल्मों में अच्छे कलाकार हैं और हम लोग फिल्मों में पूरी ईमानदारी से अच्छा काम करते हैं।

मोनालिसा ने इस दौरान देश में तेजी से आगे बढ़ रहे रीजनल सिनेमा पर भी बात की। उन्होंने कहा, अब सिर्फ हिंदी



सिनेमा ही दर्शकों का ध्यान नहीं खींच रहा, बल्कि अलग-अलग राज्यों की फिल्म इंडस्ट्री भी लगातार मजबूत हो रही हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को देश के दूसरे हिस्सों में भी दर्शक मिल रहे हैं और कलाकारों को पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है।

मोनालिसा ने उदाहरण देते हुए कहा कि साउथ इंडियन और बंगाली सिनेमा कई मामलों में लंबे समय से आगे रहे हैं और अब दूसरी क्षेत्रीय इंडस्ट्री भी तेजी से अपनी

पहचान मजबूत कर रही हैं।

अभिनेत्री ने अपने करियर को लेकर कहा, मैंने रीजनल बैकग्राउंड से आने के बावजूद काफी पहले ही नेशनल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने की कोशिश शुरू कर दी थी। करीब एक दशक से मैं नेशनल टेलीविजन का हिस्सा हूं। मैंने बिग बॉस और नच बलिए जैसे रियलिटी शोज के अलावा कई टेलीविजन सीरियल्स में भी काम किया। मैंने कई साउथ इंडियन फिल्मों में भी काम किया है।

तारा सुतारिया ने लेपर्ड प्रिंट ड्रेस में दिए किलर पोज



इस बार तारा ने 1990 के दशक के ओल्ड हॉलीवुड ग्लैमर और विंटेज स्टाइल को बेहद बोल्ड और मॉडर्न अंदाज में री-क्रिएट किया है। तस्वीरों में तारा टीएनए ब्रांड की लेपर्ड-प्रिंट वेलवेट बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रही हैं।

इस ऑफ-शोल्डर स्वीट हार्ट नेकलाइन वाली ड्रेस की फिटिंग तारा के कर्व्स और परफेक्ट फिगर को बेहतरीन तरीके से हाइलाइट कर रही है। वेलवेट फैब्रिक इस बोल्ड लेपर्ड प्रिंट को एक रॉयल और लक्जरी लुक दे रहा है।

आउटफिट को विंटेज टच देने के लिए तारा ने गले में पर्ल पेंडेंट वाला चंकी गोल्ड चोकर नेकलेस, विंटेज इयररिंग्स और हाथों में स्टेटमेंट रिंग्स कैरी की हैं।

तारा के लुक्स और मेकअप ने इस फोटो-शूट में चार चांद लगा दिए हैं। तारा ने अपने बालों को रेट्रो साइड-स्वीप्ड सॉफ्ट वेक्स में स्टाइल किया है, जो क्लासिक हॉलीवुड एक्ट्रेस की याद दिलाता है।

विंगड आइलाइनर, शेडेड आई-शैडो, न्यूड-ब्राउन लिपस्टिक और परफेक्टली स्कल्प्टेड कंटूरिंग तारा के चेहरे के फीचर्स को बेहद अट्रैक्टिव बना रहे हैं। तारा सुतारिया की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रही हैं और फैंस उनके इस वाइल्ड, बोल्ड और विंटेज अवतार की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

बॉलीवुड की स्टनिंग और ग्रेसफुल एक्ट्रेस तारा सुतारिया जब भी कैमरे के सामने आती हैं, अपने फैशन सेंस और कातिलाना अंदाज से लाइमलाइट चुरा लेती

हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने नए फोटोशूट की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं।

‘हनुमान ध्वजा स्थापना’ के साथ भव्य रामलीला महोत्सव का आगाज

हमारे संवाददाता

देहरादून। रेसकोर्स, देहरादून में श्री गुरुनानक मैदान में उत्तराखंड की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर एवं गढ़वाल की ऐतिहासिक राजधानी पुरानी टिहरी में वर्ष 1952 से चली आ रही ऐतिहासिक रामलीला की गौरवशाली परंपरा को देहरादून में पुनर्जीवित करते हुए श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952, देहरादून (पंजी.) द्वारा आयोजित “भव्य रामलीला महोत्सव-2026” का विधिवत ‘हनुमान ध्वजा स्थापना’ के साथ जन्माष्टमी के पावन अवसर पर शुभारंभ हुआ।

कार्यक्रम में गढ़वाल के पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल-दमाऊ की मंगल ध्वनि के साथ हनुमान ध्वज की परिक्रमा, पूजा-अर्चना एवं हवन किया गया। इसके पश्चात विधि-विधान से हनुमान ध्वजा की स्थापना की गई। हनुमान ध्वजा स्थापना के साथ ही रामलीला की रिहर्सल प्रारंभ करने की पुरानी परंपरा को भी आगे बढ़ाया गया। पिछले वर्ष 2025 में आयोजित भव्य



रामलीला महोत्सव को विभिन्न माध्यमों से रिकॉर्ड 82 लाख से अधिक दर्शकों ने देखा। इस व्यापक दर्शक पहुंच के साथ यह रामलीला उत्तराखंड की सबसे अधिक देखी जाने वाली रामलीला के रूप में पहचान बनाने में सफल रही। रामलीला समिति के अध्यक्ष अभिनव थापर ने कहा कि वर्ष 1952 से गढ़वाल की ऐतिहासिक राजधानी पुरानी टिहरी में चली आ रही रामलीला उत्तराखंड की प्राचीन एवं अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। इसी गौरवशाली परंपरा को देहरादून में वर्ष 2023 से निरंतर पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर हनुमान ध्वजा स्थापना के साथ रामलीला की रिहर्सल प्रारंभ करने की पुरानी परंपरा का प्रत्येक वर्ष उसी श्रद्धा और विधि-विधान के साथ पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी 1952 से चली आ रही पुरानी टिहरी की प्रसिद्ध रामलीला की चौपाई, कथा, संवाद एवं पारंपरिक मंचन शैली को उसके मूल स्वरूप में आधुनिक तकनीक के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। भव्य रामलीला महोत्सव 2026 में भव्य कलश यात्रा, भव्य मेला, बच्चों के लिए झूले एवं चरखी सहित अनेक आकर्षण होंगे। वहीं विजयादशमी के अवसर पर रावण, मेघनाथ एवं कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया जाएगा। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष अभिनव थापर, सचिव अमित पंत, गिरीश पैन्थली, नरेश कुमार, गिरीश पांडे, दुर्गा भट्ट, नीता बहुगुणा, अजय पैन्थली, नितिन डंगवाल, आशीष भूटानी, रामेन्द्र सिंह सहित समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

सू- दोकू क्र.059									
	2		6		8		3		
9		8		3		4			
							5		
5		2			7		6		
	8		4			1		3	
				9					
8			9				1		
	5			1		6		2	
		1	7				4		
नियम		सू-दोकू क्र.58 का हल							
1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।		2	6	3	8	1	4	9	7
		9	5	4	2	6	7	3	1
		8	7	1	9	3	5		6
		6	2	7	5	4	8	4	3
		3	9	8	6	7	1	2	5
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।		4	1	5	3	2	9	6	8
		5	3	2	4	8	6	7	9
		1	8	6	7	9	2	5	4
		7	4	9	1	5	3	8	2
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।									

यूकेडी ने गैरसैंण, पलायन और रोजगार के मुद्दों पर आंदोलन तेज करने का किया ऐलान

अल्मोड़ा(आरएनएस)। उत्तराखंड क्रांति दल (यूके डी) के नवनियुक्त पदाधिकारियों के प्रथम अल्मोड़ा आगमन पर कार्यकर्ताओं ने भव्य रैली निकालकर उनका स्वागत किया।

गांधी पार्क में आयोजित समारोह में पार्टी नेताओं ने उत्तराखंड के मूल मुद्दों को लेकर जनसंघर्ष तेज करने का संकल्प लेते हुए संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में नवनियुक्त केंद्रीय उपाध्यक्ष दिनेश कुंजवाल, कुमाऊं मंडल प्रभारी चंदन लोधियाल, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रवि नेगी, महानगर युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष वंश कनवाल, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष देवकी कनवाल, राज्य आंदोलनकारी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष बसंत बल्लभ जोशी तथा सैनिक प्रकोष्ठ

सीएमओ ने किया सरकारी अस्पताल का निरीक्षण

काशीपुर(आरएनएस)। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव कुमार गोस्वामी ने एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संदीप दीक्षित को मरीजों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं व उपचार की जानकारी ली।

उन्होंने आपातकालीन कक्ष, सामान्य वार्ड, गहन चिकित्सा कक्ष और नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष का भी निरीक्षण किया। सीएमओ ने निर्देश दिए कि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और आवश्यक दवाइयां व उपचार समय पर उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने अस्पताल परिसर, वार्डों और विशेष रूप से शौचालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। सीएमएस को मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए स्वच्छता के उच्च मानक सुनिश्चित करने को कहा गया।

जिलाध्यक्ष चंदन सिंह मुस्यूनी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का गठन पहाड़ के लोगों के अधिकार, सम्मान, रोजगार और समग्र विकास के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन आज भी पलायन, बेरोजगारी, खाली होते गांव, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय संसाधनों पर अधिकार जैसे मूल प्रश्न जस के तस बने हुए हैं।

यूकेडी के संस्थापक सदस्य खड़ग सिंह बगड़वाल ने कहा कि पार्टी का संघर्ष सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड की अस्मिता और राज्यवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को गांव-गांव तक मजबूत कर जनसरोकारों के मुद्दों को

आंदोलन का आधार बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने, जल-जंगल-जमीन पर स्थानीय लोगों के अधिकार सुनिश्चित करने, पलायन रोकने, युवाओं के रोजगार, महिलाओं, सैनिकों एवं राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार जैसे मुद्दों पर जनआंदोलन को और मजबूत करने का संकल्प लिया। समारोह में यूके डी जिलाध्यक्ष दिनेश जोशी, केंद्रीय मंत्री गिरीश गोस्वामी, जिला उपाध्यक्ष सुजीत टम्टा, विनय किरौला सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

चार महीनों में चारों धामों में 93.25 प्रतिशत प्लास्टिक हुआ रिकवर

ऋषिकेश (आरएनएस)। चारधाम में प्लास्टिक कलेक्शन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड स्क्रीम चलायी गई। जिसके तहत इस साल 19 अप्रैल से 26 अगस्त के बीच चारधाम यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों ने रीसाइक्लिंग के लिए 1० लाख से ज्यादा कंटेनर वापस किए हैं। उत्तकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि इस सीजन में गंगोत्री में लगभग 2.73 लाख कंटेनर वापस किए गए, जिसका रिकवरी रेट 97 प्रतिशत रहा-जो पूरी यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा है-और यमुनोत्री में 9० प्रतिशत रिकवरी के साथ 1.49 लाख से ज्यादा कंटेनर वापस किए गए। भागीरथी और यमुना के स्रोत होने के कारण ये दोनों जगहें पर्यावरण के लिहाज से बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए डीडीआरएस प्रोग्राम के ज़रिए तीर्थयात्रियों की इतनी बड़ी भागीदारी वाकई उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि बीते चार महीने में बद्रीनाथ धाम से 3,०4,771 एकत्रित कंटेनर, गंगोत्री से 2,72,864 कंटेनर, केदारनाथ से 2,9०,273 एवं यमुनोत्री धाम से 1,49,292 कंटेनर एकत्रित हुए। चारों धामों में कुल एकत्रित कंटेनर 1०,17,2०० है, जिसक वसूली प्रतिशत- 93.25 प्रतिशत रहा।कुल

कलेक्शन में सबसे बड़ा हिस्सा बद्रीनाथ का रहा, जो कुल रकम का लगभग एक-तिहाई था। इसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री का नंबर आता है। तीर्थयात्रा का सीज़न नवंबर तक चलने और चारों रास्तों पर यात्रियों की आवाजाही जारी रहने के कारण, अधिकारियों को उम्मीद है कि कुल कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी।

पोल्ट्री वैली फार्मों का निरीक्षण किया

चमोली(आरएनएस)। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने भटोली क्षेत्र में पोल्ट्री वैली फार्मों का निरीक्षण किया। उन्होंने कुक्कुट पालकों को फार्म के रख-रखाव, साफ-सफाई और पक्षियों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सुझाव दिए। निरीक्षण में सेम गांव का पोल्ट्री फार्म अच्छी स्थिति में मिला।

उन्होंने भविष्य में इसके विस्तार के लिए भी प्रोत्साहित किया। पोल्ट्री वैली के तहत क्षेत्र में दो एमपीयू संचालित हैं। इनमें एक खंडूड़ा और दूसरा सेम गांव में है। बिष्ट ने अन्य अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही कुक्कुट पालकों को परामर्श और सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी कहा।

एसटीएच में कान के ऑपरेशन हेतु एक साल तो टॉन्सिल व थायराइड के लिए 4 से 6 महीने की वेटिंग

हल्द्वानी (आरएनएस)। डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल (एसटीएच) में यदि किसी मरीज को कान का ऑपरेशन कराना है, तो उसे एक साल बाद की तारीख मिल रही है।

वर्तमान में 1,००० से अधिक मरीज ऑपरेशन की प्रतीक्षा सूची में हैं। वहीं, टॉन्सिल और थायराइड के ऑपरेशन के लिए भी मरीजों को चार से छह महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नाक, कान और गला (ईएनटी) रोगों से पीड़ित मरीजों की ओपीडी में रोजाना उमड़ रही भीड़ के कारण सर्जरी की वेटिंग लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है।

2०० की ओपीडी, औसतन आठ ऑपरेशन रोज- एसटीएच के ईएनटी विभाग में पूरे कुमाऊं से मरीज पहुंचते हैं। प्रतिदिन औसतन 2०० से अधिक मरीजों की ओपीडी होती है। इस भारी दबाव के बीच डॉक्टर रोजाना औसतन 8 ऑपरेशन कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि आपातकालीन (इमरजेंसी) स्थिति में आने वाले गंभीर मरीजों को इंतजार नहीं करना पड़ता। उनका इलाज और ऑपरेशन तुरंत किया जाता है।

पर्याप्त डॉक्टर मौजूद- ईएनटी विभाग में नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के मानकों के अनुसार 12 पीजी, दो सीनियर रेजिडेंट, तीन असिस्टेंट प्रोफेसर, एक

एसोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर तैनात हैं। डॉक्टरों की पर्याप्त टीम होने के बावजूद बुनियादी ढांचे की कमी आड़े आ रही है। यदि अस्पताल प्रशासन विभाग को एक अतिरिक्त ऑपरेशन थिएटर (ओटी) और आवश्यक आधुनिक संसाधन उपलब्ध मिलें, तो मौजूदा वेटिंग पीरियड को आधा किया जा सकता है।

निजी अस्पतालों में 5० हजार का ऑपरेशन, एसटीएच में निःशुल्क- विशेषज्ञों के अनुसार, नाक, कान और गले का कोई भी ऑपरेशन निजी अस्पताल में कम से कम 5० हजार में होता है, जबकि एसटीएच में आयुष्मान कार्ड के तहत यह निःशुल्क किया जाता है।

मुस्कुराइए आप दून में हैं...!

◆अस्पताल गये दम्पति का वाहन यातायात पुलिस ने उठाया, हंगामा

संवाददाता

देहरादून। दून की यातायात पुलिस काफी तेज होती दिखायी दे रही है। अस्पताल गये दम्पति की कार टो कर आफिस ले आये। दम्पति ने जमकर हंगामा किया।

मिली जानकारी के अनुसार एक दम्पति अस्पताल गये और उन्होंने अपने वाहन को नियमानुसार सफेद लाईन के अन्दर खड़ा किया था। लेकिन जब वह बाहर आये तो अपने वाहन को वहां न पाकर काफी परेशान हुए। आसपास के लोगों ने उनको बताया कि उनके वाहन को यातायात पुलिस टो कर ले गयी है। जिसके बाद दम्पति ने यातायात कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया और पुलिस पर उत्पीडन का आरोप लगाया। जिसके बाद वहां पर भीड़ एकत्रित हो गयी। समाचार लिखे जाने का समस्या का हल क्या हुआ इसका पता नहीं लग सका। इसी लिए कहते हैं मुस्करायें आप देहरादून में हैं।



बेचेहरा दल, बेहिसाब चंदा!

◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

के वर्षों में संदिग्ध राजनीतिक चंदे को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी सामने आई है। यह पूरा विवाद राजनीतिक व्यवस्था के सामने एक असहज सवाल रखता है। क्या राजनीतिक दल केवल चुनाव लड़ने वाली संस्थाएं हैं या वह वित्तीय लेनदेन का भी माध्यम बन सकते हैं? अगर किसी दल को करोड़ों रुपये मिलते हैं, तो जनता को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि पैसा किसने दिया, क्यों दिया, किस उद्देश्य से दिया गया और उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ।

राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता केवल लेखा-जोखा नहीं है। यह सीधे-सीधे लोकतंत्र में जनता के भरोसे का सवाल है। चुनाव में हार-जीत लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अगर चुनावी राजनीति से लगभग गायब संगठन करोड़ों की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में दिखाई देने लगे, तो फिर चुनाव आयोग, आयकर विभाग और अन्य नियामक संस्थाओं के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये राजनीतिक दल जनता की आवाज हैं या पैसे के उस खेल का पर्दा, जो राजनीति के नाम पर चलता है?

दिल्ली के ‘दिग्गजों’ से गरमाएगा पहाड़..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

भाजपा और कांग्रेस के बीच बढ़ती सीधी टक्कर के बीच क्षेत्रीय दलों के लिए भी चुनौती बढ़ेगी। उत्तराखंड क्रांति दल समेत छोटे राजनीतिक दल पहाड़, राज्य की अस्मिता, रोजगार और पलायन जैसे सवालों के सहारे अपनी जमीन बचाने की कोशिश करेंगे। इन दलों की भूमिका कई सीटों पर निर्णायक हो सकती है। यही वजह है कि बड़े दल भी क्षेत्रीय समीकरणों को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं होंगे।

राष्ट्रीय नेताओं के दौरो के साथ प्रदेश की सियासत में शक्ति प्रदर्शन का दौर भी तेज होगा। एक बड़ी रैली के जवाब में दूसरी रैली, एक बड़े बयान के जवाब में पलटवार और एक राजनीतिक मुद्दे के जवाब में दूसरा मुद्दा, यह सिलसिला अगले कई महीनों तक चलने की पूरी संभावना है। 2027 की चुनावी लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके संकेत साफ दिखाई देने लगे हैं। दिल्ली से उतरते बड़े चेहरे अब उत्तराखंड की सियासी जमीन पर अपने-अपने दांव चलेंगे। असली सवाल यह है कि इन दांवों में पहाड़ के मुद्दे भारी पड़ेंगे या राष्ट्रीय राजनीति का शोर?

दलों के बीच राजनीतिक ‘शब्दयुद्ध’...

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

नेताओं के बयानों से आगे राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस प्रकरण को उठाता है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।

भाजपा के लिए स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड को लंबे समय से हिंदुत्व और धार्मिक पर्यटन की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। चारधाम, समान नागरिक संहिता और धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दों के बीच रामलीला मैदान विवाद विपक्ष को भाजपा के व्यापक राजनीतिक मांडल पर सवाल उठाने का अवसर देता है। यदि कांग्रेस इस मामले को अन्य चुनावी राज्यों तक ले जाती है तो भाजपा को एक साथ दो मोर्चों पर जवाब देना पड़ेगा। उत्तराखंड में स्थानीय विवाद का राजनीतिक समाधान और दूसरे राज्यों में उसके राष्ट्रीय नैरेटिव का जवाब। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा अवसर यह है कि वह इस विवाद को केवल आरोप-प्रत्यारोप में फंसे से बचाकर कानून के समान अनुप्रयोग और सामाजिक सद्भाव के सवाल से जोड़े। लेकिन पार्टी के लिए खतरा भी उतना ही बड़ा है। यदि अभियान अत्यधिक धार्मिक रंग लेता है तो भाजपा इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के पुराने आरोपों से जोड़ सकती है। इसलिए कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से प्रभावी रास्ता यही होगा कि वह व्यक्ति या समुदाय विशेष के खिलाफ आरोप लगाने के बजाय प्रशासन की भूमिका, कानून के राज और संवैधानिक मूल्यों पर सवाल केंद्रित करे। रामलीला मैदान का विवाद अभी उत्तराखंड की राजनीति में ही गर्म है, लेकिन विधानसभा चुनावों का मौसम इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सकता है। कांग्रेस के लिए यह महज एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि भाजपा के खिलाफ अपने व्यापक नैरेटिव को धार देने का अवसर है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितनी दूर तक ले जाती है और भाजपा इसका जवाब किस राजनीतिक भाषा में देती है।

श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के बीच सम्पन्न हुआ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी समारोह

संवाददाता

टिहरी। श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के बीच श्रीकृष्ण जन्माष्टमी समारोह सम्पन्न हुआ।

पुलिस परिवार द्वारा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पुलिस लाइन चंबा में भव्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, पुलिस परिवारों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। पूरा पुलिस लाइन परिसर श्रीकृष्ण भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर नजर आया।

कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल श्रीमती श्वेता चौबे ने अपने पति मणिकांत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अभिसूचना, अभिसूचना मुख्यालय उत्तराखंड, देहरादून एवं अपने पुत्र के साथ पुलिस लाइन परिसर में स्थापित लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा-अर्चना की तथा भगवान श्रीकृष्ण के झूले को झुलाकर जन्मोत्सव की परंपरा निभाई। इस अवसर पर उन्होंने जनपदवासियों एवं पुलिस परिवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जनपद के



विभिन्न थानों एवं फायर सर्विस की ओर से आठ मनमोहक एवं आकर्षक झांकियां तैयार की गईं। झांकियों में भगवान श्रीकृष्ण के जीवन एवं उनकी लीलाओं को विभिन्न रचनात्मक माध्यमों से प्रस्तुत किया गया। पुलिस लाइन पहुंचने वाले लोगों के लिए ये झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। लोगों ने झांकियों के साथ सेल्फी लेकर जन्माष्टमी के उत्सव को यादगार बनाया। समारोह में पुलिस लाइन चंबा के पुलिस परिवारों तथा विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। गीत, नृत्य एवं श्रीकृष्ण की लीलाओं पर आधारित प्रस्तुतियों ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों एवं पुलिस परिवारों की प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का सांस्कृतिक एवं

संगीतमय पक्ष उस समय और अधिक जीवंत हो उठा, जब सुप्रसिद्ध गायक श्री किशन महिपाल एवं सुश्री मंजू नौटियाल ने अपनी प्रस्तुतियां दीं। दोनों कलाकारों के लोकप्रिय गीतों ने कार्यक्रम में मौजूद पुलिसकर्मियों, पुलिस परिवारों एवं स्थानीय नागरिकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। देर तक चले इस संगीतमय कार्यक्रम का दर्शकों ने भरपूर आनंद लिया। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी समारोह में मणिकांत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अभिसूचना, अभिसूचना मुख्यालय उत्तराखंड, देहरादून, सुश्री वरुणा अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी टिहरी गढ़वाल, दयाराम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढ़वाल, दीपक सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल, चंद्रमोहन सिंह, क्षेत्राधिकारी टिहरी, सुरेंद्र सिंह भंडारी, क्षेत्राधिकारी नरेंद्रनगर, संजीवा कुमार, मुख्य

आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों ने मांगों को लेकर दिया धरना

संवाददाता

देहरादून। सीटू से सम्बद्ध आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों ने अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आज यहां सीटू से संबद्ध उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री यूनियन ने उत्तराखंड के विधायकों को ज्ञापन देने के कार्यक्रम के अवसर ट्रांजिट हॉस्टल के बाहर रोकने के खिलाफ गेट पर ही धरना दिया तत् पश्चात तहसीलदार वीरेंद्र रावत के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जिस पर उनके द्वारा सभी विधायकों को ज्ञापन भेजने के आश्वासन के साथ धरना समाप्त किया गया।

बीआरपी/ सीआरपी कार्मिकों को दो माह से वेतन नहीं: मोर्चा

संवाददाता

देहरादून। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि बीआरपी/सीआरपी कार्मिकों को दो माह का वेतन नहीं मंत्री शायद कोमा में है।

आज यहां जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश भर में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्य कर रहे लगभग 750 बीआरपी- सीआरपी कार्मिकों को दो माह से वेतन नहीं मिल पाया, लेकिन गैर जिम्मेदार विभागीय मंत्री धन सिंह रावत को इन कार्मिकों की कोई चिंता नहीं है। कार्मिकों का गुजर- बसर कैसे हो रहा है, इन्होंने मकान का किराया चुकाया नहीं चुकाया, बच्चों की फीस भरी नहीं भरी इससे मंत्री का कोई वास्ता नहीं है। प्रतीत होता है कि मंत्री गहरी नींद /कोमा में चले गए हैं। इन कार्मिकों के मामले में शिक्षा विभाग समय रहते



भारत सरकार से क्यों समन्वय स्थापित नहीं करते, जिससे समय पर कार्मिकों को वेतन मिल जाए। आलम यह है कि मंत्री धन सिंह रावत को सिर्फ अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाने की चिंता है। सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री को क्यों ढो रही है। क्यों इन पर प्रतिमाह लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है। क्यों इनको निकाल बाहर नहीं किया जा रहा। आज

तक इन मंत्री द्वारा अपने अधीन विभागों के तहत कार्य कर रहे कभी किसी कर्मचारी वर्ग का भला नहीं कर पाये। मोर्चा ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री के खिलाफ आंदोलन करेगा। मोर्चा मुख्यमंत्री से मांग करता है कि ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री धन सिंह रावत को मंत्रिमंडल से निकल बाहर करें।

पत्रकार वार्ता में हाजी असद व प्रवीण शर्मा पिन्नी मौजूद थे।

कलेक्ट्रेट में मस्जिद पर चला बुलडोजर

◆ सपा सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट, भारी पुलिस बल तैनात



हमारे संवाददाता सहारनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एक मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर आज सुबह भारी राजनीतिक और सामाजिक हलचल देखने को मिली। प्रशासन ने सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश और पहली अपील खारिज होने के बाद मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर चला दिया गया। सुबह-सुबह हुई इस बड़ी कार्रवाई के दौरान कलेक्ट्रेट और आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं, इस घटनाक्रम के बीच सहारनपुर जाने की तैयारी कर रहीं कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा

हसन को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया, जिससे इलाके में राजनीतिक सरगर्मी और तनाव दोनों बढ़ गए हैं। कार्रवाई के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। कलेक्ट्रेट परिसर और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पांच कंपनी पीएसी और आरआरएफ तैनात रही। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भ्रामक खबर या अफवाह फैलने से रोकने के लिए पुलिस की साइबर सेल को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं कार्रवाई की जानकारी मिलते ही कैराना की सपा सांसद इकरा हसन ने

सहारनपुर जाकर अधिकारियों से मिलने का फैसला किया, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कैराना स्थित आवास पर ही रोक दिया। भारी पुलिस बल ने उनके घर पहुंचकर उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। सांसद ने सवाल किया कि क्या चुने हुए जनप्रतिनिधि का जनता के मुद्दों पर अधिकारियों से मिलना भी अपराध है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को रोककर जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती। बता दें कि सहारनपुर जिलाधिकारी परिसर में स्थित इस मस्जिद को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चला आ रहा था। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान मस्जिद के निर्माण को सरकारी जमीन पर अवैध पाया गया था। इसके खिलाफ मस्जिद कमिटी ने उच्च स्तर पर पहली अपील भी दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज करते हुए पुराने फैसले को बरकरार रखा। सहारनपुर मंडल के डीआईजी अभिषेक सिंह ने स्पष्ट किया कि प्रशासन ने ध्वस्तीकरण से पहले सभी विधिक और निर्धारित प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन किया है।

ट्रक की चपेट में आकर 84 वर्षीय बुजुर्ग की मौत!

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। सड़क हादसे में आज सुबह एक ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार 84 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गयी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। हालांकि घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जिसकी तलाश जारी है।

सड़क हादसे का यह मामला आज सुबह गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में ईदगाह चौक के पास द्वारकाधीश मंदिर के निकट घटित हुआ है। यहां एक बुजुर्ग की स्कूटी एक ट्रक की चपेट में आ गई। हादसा इतना गंभीर था कि बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान कामेश्वर प्रसाद



त्यागी (84 वर्ष), पुत्र सागवा सिंह त्यागी, निवासी दीनदयाल, भगवती हॉस्पिटल के पास, रुड़की के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आज सुबह वह अपनी स्कूटी से किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे। जैसे ही वह ईदगाह चौक के पास पहुंचे, उनकी स्कूटी ट्रक की चपेट में आ गई। हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग तत्काल घटनास्थल की ओर दौड़े। लोगों को अपनी ओर आता देख ट्रक चालक वाहन मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी।

सूचना मिलते ही गंगनहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया। वहीं, दुर्घटना में शामिल ट्रक को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की जानकारी दे दी है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस अब मौके से फरार हुए ट्रक चालक की तलाश में जुटी है।

मंदिर में हुई चोरी का खुलासा, तीन गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए चोरी के सामान के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवंतपुर निवासी पंकज जोशी ने राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि चोरों द्वारा पुरुकुल रोड स्थित माता भरना देवी मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां, घंटिया, दिया, अष्टधातु की थाली, शिवलिंग व नगद धनराशि चुरा ली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत घटना के खुलासे व गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद डोबाल द्वारा थाना राजपुर पर गठित पुलिस टीम को आवश्यक निर्देश दिये गये। निर्देशों के अनुपालन में पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से घटना में शामिल संदिग्धों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी एकत्रित की गई तथा प्राप्त जानकारी के आधार पर सुरागरसी पतारसी करते हुए स्थानीय तंत्र को सक्रिय किया गया। साथ ही पूर्व में इस प्रकार की घटनाओं में प्रकाश में आये अभियुक्तों की वर्तमान स्थिति की

जानकारी कर उनका भौतिक सत्यापन किया गया। पुलिस टीम द्वारा किये जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप पुलिस



टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मिली सूचना पर भंडार गांव पुरुकुल रोड के पास से उक्त चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 02 सिद्धार्थ थापा व अंकित भंडारी

को घटना में मंदिर से चुराये गये सामान व नगदी के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया कि उक्त घटना में चोरी किये गये सामान में से कुछ सामान उनके द्वारा शत्रुघ्न नाम के एक कबाड़ी को बेच दिया है, जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मंगल तिराहा पुरुकुल रोड पर जंगल के पास से प्रकाश में आये शत्रुघ्न कबाड़ी को चोरी के खरीदे हुए सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सिद्धार्थ व अंकित भण्डारी द्वारा बताया गया कि वे दोनों नशे के आदी है तथा अपने नशे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनके द्वारा रैकी करने के उपरान्त सुनियोजित तरीके से उक्त मन्दिर

में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना में चोरी किये गये सामान में से उनके द्वारा कुछ सामान शत्रुघ्न नाम के कबाड़ी को बेच कर प्राप्त धनराशि को अपने नशे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में खर्च कर दिया गया। शत्रुघ्न द्वारा बताया गया कि काठ बंगला राजपुर क्षेत्र में उसकी कबाड़ी की दुकान है तथा मुनाफा कमाने के लालच में उसके द्वारा उक्त लोगों से चोरी की घटना में प्राप्त सामान को कम दामों में खरीदा गया था, जिसे वह मंहगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में था, पर इससे पूर्व ही उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

कार खड़ी लॉरी से टकराई, आठ छात्रों की मौत!

संवाददाता

त्रिशुर। केरलम के त्रिशुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर शुक्रवार देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है। इस सड़क हादसे में आठ छात्रों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि एक कार खड़ी लॉरी से जा टकराई। सात की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ गया। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना शुक्रवार रात करीब 11.40 बजे हुई।

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हादसा कैपमंगलम के पास पनमपिक्कुनू में हुआ। मद्रास (मद्रुरै) रजिस्ट्रेशन वाली कार गुरुवायूर की तरफ से कोडुंगलूर की ओर जा रही थी। सड़क पर चल रहे निर्माण

कार्य के कारण उसी दिशा में खड़ी लॉरी से कार जोरदार टक्कर खा गई। मृतक सभी कार में सवार थे। मृतकों के तमिलनाडु के छात्र होने का अनुमान है। घटनास्थल से डिंडीगुल के पीएसएनए इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र का पहचान पत्र बरामद हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्थानीय लोगों, अग्निशमन और बचाव सेवाओं तथा पुलिस ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। अग्निशमन कर्मियों को दो घायलों को निकालने के लिए कार को काटना पड़ा। स्थानीय लोगों,



दमकल एवं बचाव कर्मियों और पुलिस द्वारा चलाए गए बचाव अभियान में युवकों को कार से बाहर निकाला गया।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य आपातकालीन दल मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव का काम शुरू किया

गया। हालांकि, टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार सभी आठ छात्रों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कार की लॉरी से टक्कर किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के समय कार की रफ्तार कितनी थी और क्या सड़क पर खड़ी लॉरी को लेकर कोई सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

पुलिस ने बताया कि उनके शवों को यहां त्रिशूर मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर में ले जाया गया। दुर्घटना में शामिल वाहन का पंजीकरण तमिलनाडु में था।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, केहरदूत से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटेर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक

कांति कुमार

संपादक

पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक

आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:

वी के अरोड़ा, एडवोकेट

बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।

मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटेर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।